



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2017/अग्रहायण 20, 1939

No. 328]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2017/AGRAHAYANA 20, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

मामला सं. एसएसआर 18/2017

विषय : कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई और इजरायल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फथेलिक एनहाइड्राइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

फा. सं. 7/19/2017-डीजीएडी.—1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई और इजरायल (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फथेलिक एनहाइड्राइड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/1/2011-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी और 28 सितंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 14/1/2011-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। राजस्व विभाग ने दिनांक 24 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 58/2012-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।

2. यतः मै. आईजी पेट्रोकेमिकल्स लि. और मै. तिरूमलाई कैमिकल्स लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित याचिका दायर की है जिसमें कोरिया गणराज्य, चीन ताइपेई और इजरायल के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का आरोप लगाया है और संबद्ध देशों से मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

शामिल देश

3. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में शामिल देश कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई और इजरायल हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "फथेलिक एनहाइड्राइड" है। फथेलिक एनहाइड्राइड फथेलिक अम्ल का एक एनहाइड्राइड है। फथेलिक एनहाइड्राइड का प्रयोग फथेलिक इस्टर्स के उत्पादन में होता है जो प्लास्टिसाइजर के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टिक उद्योग की एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती वस्तु है।

5. फथेलिक एनहाइड्राइड एक कार्बनिक रसायन है जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के उपशीर्ष 29173500 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) (में निम्नानुसार व्यवस्था है :—

“समान वस्तु ” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। दायर याचिका लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और उसे जारी रखने के लिए है और समान वस्तु का मुद्दे पर पूर्व जांचों में पहले ही विचार किया गया है। मूल जाँच में, प्राधिकारी ने पहले ही माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह याचिका मै. आईजी पेट्रोकेमिकल्स लि. और मै. तिरूमलाई कैमिकल्स लि. द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

9. भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक भी हैं। यद्यपि एस आई ग्रुप भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है; एशियन पेंट्स ने बिल्कुल हाल में जुलाई, 2017 में अपना संयंत्र बंद कर दिया है। इसके अलावा, एशियन पेंट्स ने अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत की सीमा तक आबद्ध खपत के लिए संबंधित उत्पाद का उत्पादन किया है।

10. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 89 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

11. यतः याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार विस्तृत याचिका दायर की है, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

जाँच अवधि

12. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में अक्टूबर 2016 - सितंबर, 2017 (12 महीने) है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अक्टूबर 2013 – सितंबर, 2014, अक्टूबर 2014 – सितंबर, 2015, अक्टूबर 2015 – सितंबर, 2016 और जाँच अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए पीओआई से आगे के आकड़ों की भी जाँच की जा सकती है।

प्रक्रिया

13. इस समीक्षा में दिनांक 29 जून, 2011 की अधिसूचना सं 14/1/2011-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे) मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम)।

14. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
dgad.india@gov.in

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है, वह भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नलिखित दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रति भी होनी चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTIDUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2017

Case No. SSR 18/2017

Subject : Initiation of Anti-Dumping Sun Set Review investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel

F. No. 7/19/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) initiated anti dumping investigations on imports of “Phthalic Anhydride” (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel (hereinafter also referred as the subject countries) vide Notification No. 14/1/2011-DGAD, dated 29th April, 2011, and recommended imposition of definitive anti dumping duty vide Notification No. 14/1/2011-DGAD, dated 28th September, 2012. The Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from the subject countries vide Notification No. 58/2012-Customs, dated 24th December, 2012.

2. Whereas, M/s IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. (*hereinafter referred to as ‘petitioners’*) have filed a duly substantiated petition before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Country Involved

3. The subject countries in the present sunset review investigation are Korea RP, Chinese Taipei and Israel.

Product under Consideration and Like Article

4. The product under consideration in the present investigation is “Phthalic Anhydride”. Phthalic anhydride is an anhydride of Phthalic Acid. Phthalic Anhydride is used to produce Phthalate esters, which function as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry.

5. Phthalic anhydride is an organic chemical classified under Chapter 29 subheading 29173500 of the Custom Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. Rule 2(d) with regard to ‘like article’ provides as under: -

“‘like article’ means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;”

7. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods produced by them and exported from the subject countries. The product under consideration produced by the petitioners and imported from the subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The petition filed is for the review and continuation of the anti-dumping duties in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the original investigations, the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the same imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

8. The petition has been filed by M/s IG Petrochemicals Ltd. and M/s Thirumalai Chemicals Ltd. The petitioners have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India.

9. There are two more producers of the subject goods in India. While SI Group also produces the subject goods; M/s Asian Paints Ltd. have permanently shut down their plant very recently in July, 2017. Further, M/s Asian Paints Ltd. had produced the product concerned for captive consumption to the extent of 50% of their production.

10. It is seen that the production of the petitioners is 89% of the total Indian production. The petitioners are the majority producers of the subject goods in India and are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules of Anti-Dumping Rules.

Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty

11. Whereas the petitioner has filed a detailed petition in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) is October, 2016 – September, 2017 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods October 2013 – September, 2014, October, 2014 – September, 2015, October 2015 – September, 2016 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure

13. The present sunset review covers all aspects of Notification No. 14/1/2011-DGAD, dated 29th June, 2011 (final findings of the original investigation).

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

15. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001
dgad.india@gov.in

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

Time Limit

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

24. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority